

"मुझे अखबार निकालने दो तो मैं इस बात की परवाह नहीं करता कि कौन धर्म का नियामक है और कौन कानून का निर्माता"—वेडेल फिलिप्पा

दैनिक भारतीय बस्ती

बस्ती 1 फरवरी 2025 शनिवार

सम्पादकीय

सरकारी स्कूल और शिक्षा

सरकारी विद्यालयों में दाखिले और पढ़ाई—लिखाई के स्तर को लेकर प्रायः अस्तोक्ष ही जाताया जाता रहा है। मगर इस बार ग्रामीण क्षेत्रों के सरकारी स्कूलों की वार्षिक शिक्षा स्थिति रपट यानी ‘असर’ में यह तथ्य उजागर हुआ है कि सरकारी स्कूलों में दाखिले का स्तर फिर से कोविड काल के पहले के स्तर पर पहुँच गया है, मगर उनमें पढ़ाई—लिखाई का स्तर कुछ बेहतर हुआ है। गौरतलब है कि २०२० साल से पहले छह से चौदह वर्ष आयुवर्ग के बच्चों का सरकारी स्कूलों में नामांकन हर वर्ष बढ़ रहा था।

२००६ से २०१८ के बीच सरकारी स्कूलों में बच्चों का दाखिला १६.७ फीसद से बढ़ २०१४ तक ३०.८ फीसद पर पहुँच गया था। फिर २०१८ तक इसी स्तर पर बना रहा। मगर कोराना काल में सरकारी स्कूलों में छह से चौदह वर्ष आयु के बच्चों का अनुपात २०१८ के ६५.६ फीसद से बढ़ कर २०२२ में ७२.९ हो गया। मगर बीते वर्ष में यह अनुपात फिर से २०१८ के स्तर पर पहुँच गया, यानी ६६.८ फीसद पर वापस आ गया है।

ग्रामीण क्षेत्र के सरकारी स्कूलों में बच्चों के नामांकन में कमी आने का एक कारण निजी स्कूलों की तरफ लोगों का फिर से बढ़ता रुझान बताया जा रहा है। जाहिर है, लोगों का सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर भरोसा कायम नहीं रह पाया है। कोराना काल में इसलिए बहुत सारे लोगों ने अपने बच्चों को निजी स्कूलों से निकाल कर सरकारी स्कूलों में डाला था कि उस वक्त उनकी कमाई बंद हो गई थी। इसमें एक अक्षी बात यह हुई है कि ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में शिक्षा के स्तर में थोड़ा सुधार हुआ है।

स्मार्ट फोन इस्तेमाल करने वाले बच्चों की संख्या तेजी से बढ़ी है। मगर इसमें घिटा की बात यह भी है कि स्कूलों में पांच वर्ष आयु वर्ग के बच्चों की संख्या लगातार घट रही है। २०१८ में यह आंकड़ा २५.६ था, जो २०२२ में घट कर २२.७ फीसद हुआ और २०२४ में गिर कर चिंताजनक १६.७ फीसद पर पहुँच गया। यानी ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर करने के लिए अभी बहुत कुछ किया जाना है।

आर्टिफीशियल इंटेलिजेंस वरदान या खतरा

तकनीकी विकास का उद्देश्य सदा मानवीय कामकाज को आसान और उच्चकुत्र बनाना होता है। मगर, इसके पीछे यह चुनौती भी स्वरुप जुड़ी होती है कि इसके दुरुपयोग को कैसे रोका जाए। अतःकिस के लिए हमेशा तकनीकी का उपयोग अव्यवस्था फैलाने या व्यक्थथागत दावे में सैधमारी के लिए करते हैं। कृत्रिम मेधा यानी आर्टिफीशियल इंटेलिजेंस नाम की नई तकनीक आने के बाद इसकी खिता और बढ़ गई है। शुरु से ही लोग विवेक कर रहे हैं कि कृत्रिम मेधा को प्रश्रय देने से लोगों की रचनात्मकता, निजता और विनीय सुख्खा खारे में पड़ जाएगी। इसलिए कि यह ऐसी तकनीक है, जो दुनिया पर में उपलब्ध सूचनाओं को खंगाल कर किसी भी व्यक्ति को वांछित सूचनाएं उपलब्ध करा देता है।

हालाकि एल्गोरिदम तकनीकी सूचनाओं की छानबीन पहले से ही करती आ रही है। कृत्रिम मेधा के इस्तेमाल से यह काम बड़े स्तर पर आए कई गुना अधिक तेजी से किया जा सकता है। इसलिए दुनिया भर के देश विदेश हैं कि जेटा संग्रह में सैधमारी करने वाले इस तकनीकी का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग करेंगे। यह तकनीक अभी अपने प्रारंभिक चरण में है, मगर इसका दुरुपयोग व्यापक स्तर पर दिखाई देने लगा है।

दरअसल, विश्व आर्थिक मंच के सम्मेलन में कई देशों ने रेखांकित किया कि कृत्रिम मेधा के अनियंत्रित प्रसार पर लगाम लगाने की जरूरत है। स्पेन के प्रधानमंत्री ने यूरोपीय संघ से आह्वान किया कि गलत सूचना और साइबर उन्पीड़न पर अंकुश लगाने के लिए कठोर कदम उठाया जाना चाहिए। एल्गोरिदमों में पारदर्शिता के लिए शक्तियों के विस्तार की जरूरत है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतेर्रेस ने कृत्रिम मेधा की वैश्विक चुनौती बताते हुय कड़ी चेतावनी जारी की, जैसे मानवता के लिए एक बड़ा जोखिम बताया और इस मामले में सरकारी और निजी स्तर पर एकीकृत कार्रवाई पर जोर दिया। सही है कि चिकित्सा, शिक्षा, संचार, अभियांत्रिकी आदि क्षेत्रों में कृत्रिम मेधा का सकारा योगदान हो सकता है। इससे आगे की तकनीकी विकासित करने में बहुत आसानी होगी, मगर इसके प्राथमिक चरण में ही जिस तरह वित्तीय हेराफेरी, लोगों के उन्पीड़न, गलत सूचनाएं प्रसारित कर बढा खसामनी फैलाने की कोशिशें लगातार देखी जा रही हैं, उससे चिंतित बढना वदमावित है। इसके दुरुपयोग पर अंकुश लगाने की तकनीकी विकासित करने की उन्मीद उन्हीं लोगों से करनी है, जिन्होंने इसका विकास किया है। मगर सरकारें इसके लिए केवल उनके भरोसे नहीं बैठ सकती। मानसी शिक्षाओं के बिना व्यावसायिक निरकुशता को रोकना मुश्किल ही बना रह सकता है।

जैसे—जैसे दुनिया डिजिटल तकनीक पर आश्रित होती जो रही है, हर काम डिजिटल उपकरणों और इंटरनेट से जोड़ा जाने लगा है, उसमें कुशलता बढना खतरा बन कर उभर रही है। हर रोज़ सरकारी कामों में लापरवाही फैल रही हो रहे हैं, जिन्हें साइबर सैधमाल लोगों के बैंक खातों से पैसे उड़ा लेते हैं। कृत्रिम मेधा के जरिए किसी बड़े अधिकारी, अपने ही मित्र और परिजन या फिर जाल में फंसे आदमी का भी चेहरा और आवाज चर्या कर के उससे कीज कर ली जाती है। जाने—पहचाने चेहरों का इस्तेमाल कर गलत सूचनाएं प्रसारित कर दी जाती है, जिन्हें लोगों में भ्रम और कई बार उत्तेजन फैल जाती है। भारत में ऐसी घटनाएं लगातार बढ रही हैं, जिसे लेकर प्रधामंत्री तक को सावधान रहने की अपील करनी पड़ी। उन्मीद है कि इस समस्या पर विश्व आर्थिक मंच से उठी आवाज पर संजीदगी नजर आएगी।

वित्तीय वर्ष २०२५—२६ के केंद्रीय बजट पर टिकी निगाहें

— प्रहलाद सबनानी—

वित्तीय वर्ष २०२४—२५ की पहली छमाही (अप्रैल—सितम्बर २०२४) में भारत की आर्थिक विकास दर कुछ कमजोर रही है। प्रथम तिमाही (अप्रैल—जून २०२४) में तो सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर गिरकर ५.२ प्रतिशत के निचले स्तर पर आ गई थी। इसी प्रकार द्वितीय तिमाही (जुलाई—सितम्बर २०२४) में भी सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर ५.४ प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है। इससे वित्तीय वर्ष २०२४—२५ में यह वृद्धि दर घटकर ६.६ प्रतिशत से ६.८ प्रतिशत के बीच रहने का अनुमान है, जबकि वित्तीय वर्ष २०२३—२४ में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर ८.२ प्रतिशत की रही थी। वित्तीय र्ष २०२४—२५ की प्रथम छमाही में आर्थिक विकास दर के कम होने के कारणों में मुख्य रूप से देश में सम्पन्न हुए लोक समा चुनाव है और आचार संहिता के लागू होने के चलते केंद्र सरकार के पूंजीगत खर्चों एवं अन्य खर्चों में भारी भ्रमकम कमी दु र्दिगोचर हुई है। साथ ही, देश में मासतु की स्थिति भी ठीक नहीं रही है।

केंद्र सरकार ने हालांकि मुद्रा स्थिरि पर अंकुश लगाने में सफलता तो अर्जित कर ली है परंतु उच्च स्तर पर बनी रही मुद्रा स्थीति के कारण कुल मिलाकर आम नागरिकों विशेष रूप से मध्यमवर्गीय परिवारों की खर्च करने की क्षमता पर विपरीत प्रभाव जरूर पड़ा है और कुछ म्ध्यवर्गीय परिवारों के गरीबी रेषा के नीचे जीवना यापन कर रहे परिवारों की श्रेणी में जाने का खतरा उत्पन्न हो गया है। किसी भी देश में म्ध्यमवर्गीय परिवारों की जितनी अधिक संख्या रहती है, उस देश की आर्थिक विकास दर ऊँचे स्तर पर बनी रहती है क्योंकि मध्यमवर्गीय



परिवार ही विभिन्न प्रकार के उत्पादों (दोपहिया वाहन, चारपहिया वाहन, फ्रिज, एयर कंडीशनर जैसे उत्पादों एवं नए प्लेटेस्ट एवं भवनों आदि) को खरीदने पर अपनी आय के अधिक भाग का उपयोग करता है। इससे आर्थिक चक्र में तीव्रता आती है और इन उत्पादों की बाजार में मांग के बढ़ने के चलते इनके उत्पादन को विभिन्न कम्पनियों द्वारा बढ़ाया जाता है, इससे इन कम्पनियों की आय एवं लाभप्रदता में वृद्धि होती है एवं देश में रोजगार के नए अवसर निर्मित होते हैं।

भारत में पिछले कुछ समय से मध्यमवर्गीय परिवारों की व्यय करने की क्षमता पर विपरीत प्रभाव पड़ है अतः दितिक १ फरवरी २०२५ को केंद्र सरकार की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन से अब यह अक्षा की राह रही है कि वे वित्तीय वर्ष २०२५—२६ के केंद्र सरकार के बजट में मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए विशेष रूप से आय कर में छूट की घोषणा करेंगी। देश के कई अर्थशास्त्रियों का तो यह भी कहना है कि न केवल आय कर में बल्कि कारपोरेट कर में

भी कमी की घोषणा की जानी चाहिए। इनकोसि के संस्थापक सदस्यों में शामिल श्री मोहनदास पटेल का तो कहना है कि १५ लाख से अधिक की आय पर लागू ३० प्रतिशत की आय कर की दर को अब १८ लाख से अधिक की आय पर लागू करना चाहिए। वर्तमान में लागू ७.७५ लाख रूपर की राशि से बढ़ाकर १० लाख रूपर कर देना चाहिए। आयकर की धारा ८०सी के अंतर्गत किए जाने निवेश (फलों एवं सब्जियों आदि) के कुछ महंगे होने के चलते ही उच्च स्तर पर आ जाती है जबकि कोर मुद्रा स्थीति की दर तो अब नियंत्रण में आ चुकी है। खाद्य पदार्थों की महंगाई को ब्याज दरों को उच्च स्तर पर बनाए रखकर कम नहीं किया जा सकता है। अतः भारतीय रिजर्व बैंक को अब इस ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

फरवरी २०२५ माह में ही भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मोनेटरी पॉलिसी की घोषणा भी होने जा रही है। भारतीय रिजर्व बैंक से अब यह अक्षा की राह रही है कि वे पेपो दर में कम से कम २५ अथवा ६० आधार बिंदुओं की कमी तो अवश्य करेंगे। क्योंकि

पानी में जहर की राजनीति

—डॉ.वेदप्रकाश—

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल आरोपजीवी राजनेता हैं। शायद ही कोई दिन ऐसा जाता होगा जब वे स्वयं अव्या उचित पार्टी के बड़े नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस न करते हों। उनके पास दूसरी सोच पर आरोपों एक लंबी सूची है। सर्वविधित है कि राजनीति में अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी की पध्दतान की संस्कृति को बढ़ावा देने वाले, कमी एलजी पर तो कमी केंद्र सरकार पर आरोप लगाने वाले, ख्याली पीढा बनाने वाले, बड़े—बड़े सपने दिखाने वाले के रूप में रही

यह भी सर्वविधित है कि समाजसेवी अन्ना हजारे आदि का लाभ उठाते हुए आम आदमी पार्टी अस्तित्व में आई। भ्रष्टाचार खत्म करो,साफ़ खुशरी राजनीति बनाओ, दिल्ली की स्टीटाउरबलई करणो, दिल्ली की शिक्षा का मॉडल अच्छा बनाओ, कूड़े के पहाड़ को खत्म कर दो, हरि दिल्ली को फ्री वात—फाई देओ, पूर घर में २४ घंटे पानी, यमुना की सफाई और विश्व स्तरीय क्रीडो आदि नारों के सहारे वे दिल्ली की राजनीति में जम गए लेकिन राजनीति का अनुभव न होने से उन विचारों की समुचित विश्द व दृष्टि न होने से दिल्ली में मुश्त और केवल मुश्त की संस्कृति से अनेक प्रकार की समस्याएं खड़ी होती चली गईं। जनकल्याण के अनेक आमजन काम ऐसे भी पड़े रहे। जब कमी उनका चर्चा भी हुई तो स्वयं अरविंद केजरीवाल दिल्ली के एलजी पर अव्या केंद्र सरकार पर पैसा न देने का आरोप लगाकर पल्ला झाड़ते रहे।

हाल ही में आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में जन संकट की स्थिति पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि हरियाणा की भाजपा सरकार जान बूझ कर दिल्ली में जहरिली पानी भेज रही है। उन्होंने नरेंद्र सरकार की साजिश करार दिया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली की जन्ता भाजपा को वोट नहीं दे रही है इसलिए हरियाणा की भाजपा सरकार उन्पे हरिद्वार मिला पानी पिलाकर मरना चाहती है। हरियाणा की भाजपा की सरकार ने दिल्ली वालों की पानी की आपूर्ति को बाधित करने के लिए हरियाणा से अपनी कीडियों का सार प्रदूषण डीडी ८ से यमुना नदी में छोड़ना शुरू कर दिया है। इससे

है कि देश में वन नेशन वन इलेक्शन कानून को शीघ्र ही लागू किया जाना चाहिए क्योंकि बार बार देश में चुनाव होने से केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा आचार संहिता के लागू होने के चलते अपने बजटीय खर्चों को रोक दिया जाता है जिससे देश का आर्थिक विकास प्रभावित होता है। अतः वित्तीय वर्ष २०२५—२६ के लिए लोक सभा में पेश किए जाने वाले बजट में पूंजीगत खर्चों को बढ़ाने पर गम्भीरता दिखाई जाएगी। हालांकि वित्तीय वर्ष २०२२—२३ के बजट में ७.५० लाख करोड़ रूपर के पूंजीगत खर्चों का प्रावधान किया गया था, वित्तीय वर्ष २०२३—२४ के बजट में १० लाख करोड़ रूपर एवं वित्तीय वर्ष २०२४—२५ में ११.११ लाख करोड़ रूपर के पूंजीगत खर्चों का प्रावधान किया गया था। अब वित्तीय वर्ष २०२५—२६ के लिए कम से कम १५ लाख करोड़ रूपर के पूंजीगत खर्चों का प्रावधान किये जाने की सम्भावना व्यक्त की जा रही है। इससे देश में धीमी पड़ रही आर्थिक गतिविधियों को तेज करने में सहायता मिलेगी और रोजगार के करोड़ों नए अवसर भी निर्मित होंगे, जिसकी वर्तमान समय में देश को अत्यधिक आवश्यकता भी है।

विभिन्न राज्यों द्वारा चलाई जा रही प्रौद्योगिकी योजनाओं पर भी अब अंकुश लगाए जाने के प्रयास किए जाते चाहिए। इन योजनाओं से देश के आर्थिक विकास को लाभ कम और नुकसान अधिक होता है। केरल, पंजाब, सिमाचल प्रदेश एवं दिल्ली की स्थिति हम सबसे सामने है। इस प्रकार की योजनाओं को चलाने के कारण इन राज्यों के बजटीय घाटे की स्थिति दयनीय स्थिति में पहुँच गई है। पंजाब तो किसी समय पर देश के सबसे सम्पन्न राज्यों में शामिल हुआ करता था परंतु आज पंजाब में बजटीय घाटा भयावह स्थिति में पहुँच गया है। जिससे ये राज्य आज पूंजीगत खर्चों पर अधिक राशि व्यय नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इन राज्यों की न तो आय बढ़ रही है और न ही बजटीय घाटे पर नियंत्रण स्थापित हो पा रहा है। पिछले कुछ समय से भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भी कम हो रहा है। यह सितम्बर २०२० तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद का ४.३ प्रतिशत था जो अब गिरकर सकल घरेलू उत्पाद का ०.८ प्रतिशत के स्तर तक नीचे आ गया है। वित्तीय वर्ष २०२५—२६ के बजट में इस विषय पर भी गम्भीरता से विचार किया जाएगा। वित्तीय वर्ष २०१९ के बजट में कोरपोरेट कर की दरों में कमी की घोषणा की गई थी, जिसका बहुत अच्छा प्रभाव विदेशी प्रत्यक्ष निवेश पर पड़ा था और सितम्बर २०२० में तो यह बड़कर सकल घरेलू उत्पाद का ४.३ प्रतिशत तक पहुँच गया था। अब एक बार पुनः इस बजट में कोरपोरेट कर में कमी करना पर भी विचार किया जा सकता है। वित्तीय वर्ष २०२५—२६ के बजट में रोजगार के अधिक से अधिक अवसर निर्मित करने वाले उद्योगों को भी कुछ राहत प्रदान की जा सकती है क्योंकि आज देश में रोजगार के करोड़ों नए अवसर निर्मित करने की महती आवश्यकता है। विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु एवं म्ध्य उद्योगों की विशेष सुविधाएं प्रदान की जा सकती है। वैसे न तकनीकी आगति उद्योगों को भी बढ़ावा देना होगा क्योंकि वैश्विक स्तर पर भी हमारे उद्योगों को प्रतियोगी बनाना है। ग्रामीण इलाकों में आज भी भारत की लगभग ६० प्रतिशत आबादी निरक्षर करती है अतः कृषि क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्र में कुटीर एवं लघु उद्योगों पर अधिक ध्यान इस बजट के मा्थम से दिया जाना, ताकि रोजगार के अवसर प्राप्तिग इलाकों की ही निर्मित हो सके और ग्रामीणों के शहर की ओर हो रहे पलायन को रोक जा सके।

डीपसीक और अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती



—डॉ. संजय वर्मा—

अमेरिकी सत्ता पर दोबारा कब्जि होने के पहले ही दिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक चीनी एप डिक्लेरि पर अपने देश में पानी पाबंदी हटाने का ऐलान किया, तो उन्हे अस्सास नहीं रहा होगा कि एक अन्य चीनी क्रांति उनको नींद हटान करने के लिए पैदा हो गई है। यह क्रांति कृत्रिम बुद्धिमत्ता से खास किस्म के माइक्रोफिजि (ए—१०० और ए—८००) देरते ही खरीद चुके थे, लिहाजा उनका अत्यधिक किफायत से इस्तेमाल कर चोटबाँट डीपसीक बना डाला गया।

कहां तो अमेरिका इस कोशिश में था कि चीन एआई के मामले में उनका पिछलगू रहे। वरन, लेकिन लगभग और जितनी डीपसीक उससे आगे मिलेन जाय। डीपसीक आर—१ के आर्थिक फायदे—एनवीडीया से खास तस्वीर तो दुनिया देख ही चुकी है। जैसे ही अमेरिका—उपसीक के पड़वने की खबरें आईं, उसके शेयर बाजारों में तबाही का आरम्भ पैदा हो गया। इसकी वजह एआई के क्षेत्र में अमेरिकी कम्पनियों के दबदबे को चुनौती मिलना है। डीपसीक आर—१ ब्रूकिए एक मुश्त और मुश्त सोर्स सॉफ्टवेयर (एआई टूल या कहें कि चोटबाँट है), जिसे बनाने में अमेरिका की मशीनी तकनीक और माइक्रो सिप्स की बजाय उत्पन्न करते सस्ते संस्करण इस्तेमाल किए गए हैं, लिहाजा माना गया कि तकनीक के आधिकार और उसे आसामाने के जो लागत और कीमत अमेरिकी कम्पनियां बताती रही हैं, वे बढा—बढाकर बताते गईं।

मिसाल के तौर पर अमेरिकी कम्पनी ओपन एआई ने चोटजीपीटी को जिस लागत में बनाया था, डीपसीक के निर्माण की लागत उससे दस गुना कम (६० लाख डॉलर अथवा तीन कीबै ५२ करोड़ रुपये) आई है। इस चीनी कम्पनी ने साबित कर दिया कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता वाले बड़ी काम बड़े सस्ते में और कई मामलों में मुश्त से हो सकते हैं जिनके लिए अमेरिकी कम्पनियां वसंतियों गुना ज्यादा



पैसा ले रही हैं। हालांकि, कुछ का कहना है कि यह दावा करना कि एआई का कोई बेहद शानदार प्रकं १ बहुत कम प्रसे में हो गया है—एक भू—रचनातीक योजना का हिस्सा हो सकता है। ऐसा कहने के पीछे अमेरिका के खिलाफ आर्थिक युद्ध करने की मत्ता काम कर रही होगी।

दरअसल, कृत्रिम रूप से कम लागत का दावा करने का अर्थ यह साबित करना है कि अमेरिकी कम्पनियां खत्म रूप से लागत और कीमतें कई गुना बढ़ाकर बताती हैं। लेकिन यदि वही काम दस—बीस गुना कम कीमत में हो सकता है, तो प्रतिस्पर्ध में आने वाली कम्पनी या तो अपने उत्पाद की कीमत उसकी बराबरी में लाते को मजबूर हो जाएगी या फिर घाटा उठाने अव्या कामकाज बंद करने को मजबूर हो जाएगी। लेकिन क्या मुश्त होने के साथ—साथ डीपसीक आर—१ चोटजीपीटी या डीपसीक के जेमाआई की तरह ही सक्षम है और उनकी बराबरी कर सकता है।

अभी दो चीजों को लेकर डीपसीक की घेराबंदी शुरू हो गई है। पहली चीज है यूएसडै—प्रेरित जाय देना या जेमा देने से इनकार कर देना। जैसे, जब डीपसीक पर सवाल पूछा गया कि चार जुन, १९८९ को तियायामने घोषाएं पर द टैकमैन कामा मशरूफ घटना का विवरण क्या है, तो डीपसीक जवाब देने से कमी काट गया। सवाल दोहराते रहने पर भी यही जवाब मिला कि वह तो एक एआई असिस्टेंट है, जिसे कोई नुकसान पहुँचाया जाये, जिसे कोई प्रश्न करने के लिए डिजाइन किया गया है। दूसरा एतजज डीपसीक को लेकर यह है कि उन्हे आप हूय पर पंजीकरण (साइड—अप) करते हैं, तो यह आपकी सारी निजी जानकारी वसंतियों चीन तक पहुँचा देगा। भारत में चीन के सोशल मीडिया एप— टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने और अमेरिकन में चीनी कम्पनी हुवाये का कारोबार रोकने के पीछे यही तर्क दिया जाता रहा है कि ये चीनी उपकरण और स्मार्ट मशीनें जासूसी करती हैं।



दिल्ली के ३० प्रतिशत लोगों को पानी का पानी नहीं मिलेगा। इस आरोप के जवाब में दिल्ली जन बोर्ड की सीईओ शिल्पा शिंदे ने आपा तन्हाई के आरोपों को भ्रामक बताया है। सही सी हरियाणा के मुख्यमंत्री नाथ सिंह ने भी कहा कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज एक बार फिर साबित किया कि घबिया और झूठ की राजनीति करने के मामले में उनका कोई सानी नहीं है। उन्होंने हरियाणा पर जो ब्रूडियद्वार, रमानेक, मगगढत और झूठे आरोप लगाए हैं, उनको लेकर हम चुनाव आयोग को शिकायत करेंगे और मानहानि का मामला दर्ज करेंगे। आरोप— ज्यवाोरस का सिसिलिया जरी है। चुनाव आयोग ने भी अरविंद केजरीवाल से यमुना के पानी में जहर घोलेने का आरोप प्रामाणित करने को कहा है। ध्यातव्य है कि यमुना लंबे समय से प्रदूषण की शिकार है। दिल्ली में यह दवा ठोस रही है। दिल्ली में यमुना के बायाव क्षेत्र में जैव संपदा पूरी तरह व्धस्त हो चुकी है। कई बड़े नालों के अतिरिक्त यमुना के बायाव क्षेत्र में छोटे—छोटे कई दर्जन नाले प्रत्यक्ष अव्या अवलम्ब रूप से सीधे गिरा रहे हैं। सीवैज ट्रीटमेंट के नाम पर आईटीओ, ओखला और कोकली आदि में जो संयंत्र लगे हैं वह आज अपूर्व हैं। दिल्ली की अनेक औद्योगिक इकाइयों का कचरा सीधे यमुना में जा रहा है। यमुना एक्शन प्लान को अंगरंगार यमुना की प्रदूषण मुक्ति हेतु जो योजनाएं बानी चाहिए थी, वे नहीं बन पाईं हैं। यमुना जल में औसंदीपनी की कमी और अनेक भाजपा को वोट नहीं दे रही है इसलिए हरियाणा की भाजपा सरकार उन्पे हरिद्वार मिला पानी पिलाकर मरना चाहती है। हरियाणा की भाजपा की सरकार ने दिल्ली वालों की पानी की आपूर्ति को बाधित करने के लिए हरियाणा से अपनी कीडियों का सार प्रदूषण डीडी ८ से यमुना नदी में छोड़ना शुरू कर दिया है। इससे

भ्रष्टाचार के कारण बढ प्रक्षिया न हो सकी। यह भी ध्यान रहे कि न तो यमुना में प्रदूषण का मामला नया है और न ही यमुना जल में अमनीया की मात्रा बढन का। चुनाव के समय यमुना की सफाई, कूड़े के पहाड़ों को खत्म करना जैसे अनेक चुनौती वाले काम भी अरविंद केजरीवाल पर कुछ काम नहीं होता है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिंसोदिया और संसदें जन सहित कई बड़े नेता घोटालों के आरोप में लगे सजा जेल काटने के बाद जमानत पर बाहर हैं। क्या दिल्ली की बढहाली की वजह ये सीधे जिम्मेवार नहीं रहे? ये दिल्ली की किसी मरदाई और न ही आगे किसी करिगे, यानी विचारणीय है लेकिन यमुना के पानी में जहर मिलाकर नरसंहार का आरोप अरविंद केजरीवाल की बीमहालद्व, इस बार चुनाव में हार के म्थ और मानसिक वित्तिदायित्वाय को प्रमाणित कर रहा है। चुनाव आयोग उनके इस आरोप पर गंभीर है। आयोग ने इस संयंत्र में केजरीवाल से पुनरा पाषा सवालों के जवाब देने को कहा है। यह भी वित्ताजनक है कि विगत लम्बे समय से जल्लि, खल्लय, शैवीतया, भाषा, सविधान, किसान, युवा, महिलाएं, केजरीवाली आदि अनेक मुद्दे पर समूचा विषय निश्चित त्थायों की पूर्ति होना सिद्ध में जहर घोलेने का प्रयास कर रहा है। भिन्न—भिन्न रूपों में भ्रम और म्थ फैलाकर आपसी सन्धामा मंग करने के प्रयास सामान्य होते जा रहे हैं। दिल्ली में अब केवल नालों में ही नहीं आदित्य शिखरी में भी जल संकट सामान्य होता जा रहा है। दिल्ली की जनसंख्या लगातार बढ रही है। यहाँ जनसंख्या के अनुपात में शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और मूलभूत सुविधाएं कम पड़ रही हैं और उन्हे समुचित रूप में व्यवस्थित करने के कोई प्रयास भी नही हो रहे हैं। यहाँ जनसंख्या को बालित तो नजर नहीं आ रहा है। पानी के माध्यम से लोगों के मन—मस्तिष्क में जहर घोलने की राजनीति घातक है।

[illegible]

सूर्य अहम मुतालिकी मुकुन्दम
जवाब दे सके या जिनके साथ कोई
और सख्त हो जा कि जवाब ऐसे
सवालता का जो सके हाज़िर हो और
जवाबदेही दवा कीजिये और हरगाह
बुरी ताश्चिख और आपक इजहार का
लिखे मुकुरर है जवाब नमिफासल
कित्तेय मुकुन्दम के जवाबोही हुई है
और आपको तास्मिह है कि छि उरी
उरी जुमना वस्तावेज को जिनको
आप अपनी जवाबदेही के रहत
इस्तेमाल करना चाहते हो पेश करें।
आपको इस्तिलाही दी जाती
है कि आप हंगोत मजकूर आप
हाज़िर न होंगे तो मुकुन्दम दगैर
हाज़िरी आपक मसमूआ और फैसला
होसिगी।
बसल्ले मेरे दरस्तलत और
मुहर अदालत के आप बतारीख